

## बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण

सतत वृद्धि और वैश्विक मंदी से लोचशीलता ने 2007-08 में अब तक भारतीय अर्थव्यवस्था के घटनाक्रमों की विशेषता बताई है। वस्तुओं की कीमतों में वैश्विक तेजी और पूंजी अंतर्वाहों में उछाल, जिसने नकदी प्रबंधन को कठिन बना दिया था, के बावजूद अर्थव्यवस्था मोटे तौर पर घरेलू मुद्रास्फीति के दबावों को काबू में रखने में सफल रही है। समग्र बृहद आर्थिक मूल सिद्धांत निरंतर विश्वास और आशावाद को प्रेरित करते रहे। सरकारी राजस्व में बेहतर वृद्धि ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएमए) के अन्तर्गत यथा अधिदेशित राजकोषीय समेकन को सुदृढ़ बनाना संभव किया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 9 प्रतिशत (औसत) के वृद्धि लक्ष्य को पूरा करने के लिए संसाधनों की व्यवस्था हेतु घरेलू बचतों और निवेश दरों में तेजी थी।

### आर्थिक वृद्धि

2. वर्ष 1999-2000 के स्थिर मूल्यों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के सीएसओ द्वारा 2007-08 में 8.7 प्रतिशत की दर से बढ़ना अनुमानित है। यह 2005-06 (अंतिम) में 9.4 प्रतिशत की उच्च वृद्धि और 2006-07 (त्वरित अनुमान) में 9.6 प्रतिशत से मामूली गिरावट प्रतिबिंबित करती है। 2007-08 में वृद्धि में गिरावट यद्यपि मामूली थी परन्तु यह बिजली, सामुदायिक सेवाओं और "व्यापार, होटल, परिवहन और संचार" की मिश्रित श्रेणी के सिवाय अधिकतर क्षेत्रों में फैली हुई है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि में गिरावट का कारण रबी फसलों में धीमी वृद्धि का होना है। विनिर्माण और भवन निर्माण की वृद्धि जो 2006-07 में 12 प्रतिशत की दर से बढ़ी वह भी 2007-08 में लगभग 2.5 प्रतिशतांक गिर गई। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (आईआईपी में यथा प्रतिबिंबित) की मंद वृद्धि विनिर्माण की मंदी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक थी। अप्रैल-नवंबर 2007 में रेलवे द्वारा माल ढुलाई, हवाई पत्तनों पर यात्रियों के संचलन और बैंक ऋण से राजस्व आय की वृद्धि में भी मंदी थी, जिसने 2007-08 के पूरे वर्ष के मूल्यांकन का आधार बनाया।

3. वर्ष 2006-07 में वृद्धि फरवरी 2007 के शुरू में 9.2 प्रतिशत पर अनुमानित थी, इसे मई 2007 में ऊपर की ओर संशोधित कर 9.4 प्रतिशत किया गया और फिर 31 जनवरी 2008 को केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी त्वरित अनुमान में 9.6 प्रतिशत किया गया। फरवरी, 2006 में जारी अग्रिम अनुदानों के अनुसार 8.1 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 2005-06 में 9.4 प्रतिशत (अंतिम) की वृद्धि का वृद्धिकारी संशोधन भी किया गया था। यह संकेत देता है कि 2007-08 के अनुदानों में वृद्धिकारी समंजन संभव है।

4. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) में देखी गई 7.8 प्रतिशत वृद्धि अब तक किसी भी योजना अवधि में सबसे अधिक है और यह 8 प्रतिशत के लक्ष्य से मामूली कम है। दसवीं योजना के दौरान वृद्धि की महत्वपूर्ण विशेषता विनिर्माण में हुआ पुनरुत्थान था। विनिर्माण की वृद्धि में तीव्र तेजी आई जो नौवीं योजना के दौरान 3.3 प्रतिशत से दसवीं योजना के दौरान 8.6 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र में वृद्धि व्यापक आधार पर बनी रही।

5. मांग की दिशा में निवेश वृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण वाहक के रूप में उभरा है। बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2002-2003 में 3.8 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 9.7 प्रतिशत हो गई और 2007-08 में इसमें 8.7 प्रतिशत होने का अनुमान था। मौजूदा बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद 2007-08 में 46,93,602 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस प्रकार चालू राजकोषीय वर्ष में बाजार मुद्रा विनिमय दर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार एक ट्रिलियन अमरीकी डालर को पार कर जाएगा। सामान्य मुद्रा विनिमय दर पर (अप्रैल-दिसंबर 2007 का औसत), सकल घरेलू उत्पाद के 2007-08 में 1.16 ट्रिलियन अमरीकी डालर पर पहुंचने का अनुमान है।

6. आर्थिक विकास, और विशेषकर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय स्तर लोगो पर हुई प्रगति का एक व्यापक प्रमात्रात्मक संकेतक है। प्रतिव्यक्ति आय की वृद्धि में बहुत तीव्र गतिवर्धन हुआ है जिसका औसत 7.2 प्रतिशत प्रतिवर्ष (2003-04 से 2007-08) रहा है, जो यह संकेत देता है कि औसत आय एक ही पीढ़ी के भीतर अब एक दशक में दोगुना हो जाएगी। प्रतिव्यक्ति निजी अंतिम खपत व्यय (पीसीपीएफसीई) में भी प्रति व्यक्ति आय की तरह ही वृद्धि हुई है। वर्ष 2003-04 से 2007-08 के दौरान प्रतिवर्ष 5.1 प्रतिशत की वृद्धि दर थी और इसके वर्ष 2007-08 में 5.3 प्रतिशत होने की संभावना है। खपत की औसत वृद्धि मुख्यतः बढ़ती बचत दरों के कारण आय की औसत वृद्धि से धीमी है।

### बचत और निवेश

7. हाल की सकल घरेलू उत्पाद की उल्लेखनीय विशेषता सकल घरेलू निवेश और बचत में तेजी से वृद्धि की प्रवृत्ति है। 1990 के दशक में हुए सुधारों से निवेश माहौल में बदलाव आया, व्यापार में विश्वास बढ़ा और उद्यमियों में आशा का संचार हुआ। जिसके परिणामस्वरूप समस्त कारपोरेट सेक्टर में प्रतिस्पर्धा धीरे-धीरे बढ़ने लगी, विनिर्माण सेक्टर का पुनरुत्थान हुआ और निवेश दर में वृद्धि

हुई। एफआरबीएमए अधिदेशित राजकोषीय सुधार मार्ग राजकोषीय समायोजनों के सम्बन्ध में सरकार विश्वनीयता बढ़ाने में भी सहायक था। इससे अर्थव्यवस्था की दीर्घावधिक वृहत् आर्थिक स्थिरता के बारे में व्याप्त अवधारणाओं में सुधार हुआ। संतुलित कर दरों के साथ-साथ बिक्री की वृद्धि में उछाल ने कारपोरेट सेक्टर के आंतरिक प्रोद्भवन को बढ़ाया। उन्नत निवेश माहौल और सुदृढ़ वृहत् आधार के परिणामस्वरूप विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में तेजी आयी। इसके फलस्वरूप निवेश दर में वृद्धि हुई जो 2002-03 में जीडीपी के 25.2 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में जीडीपी का 35.9 प्रतिशत हो गई। अधिक निवेश घरेलू बचतों को आत्मसात करने में समर्थ था और विदेशों से पूंजी अंतर्वाहों को आत्मसात करने की ललक उत्पन्न करने में समर्थ था। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचतों में निरन्तर सुधार होता रहा जो दसवीं योजना के दौरान 31.4 प्रतिशत के औसत से 2002-03 में 26.4 प्रतिशत से बढ़कर 2006-07 में 34.8 प्रतिशत हो गयी। बचत-निवेश में अन्तर जो 2001-2004 के दौरान सकारात्मक बना रहा, उसके बाद ऋणात्मक हो गया। बचत-निवेश संतुलन में इस उलटफेर को 2005-06 और 2006-07 के दौरान मांग में सामान्य से अधिक वृद्धि से उत्पन्न होने वाले घरेलू आपूर्ति-मांग संतुलन में सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

### समावेशी विकास

8. तीव्रतर आर्थिक विकास से रोजगार सृजन और गरीबी में कमी इन दोनों दृष्टियों से अधिक समावेशी विकास आरम्भ हुआ है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 61 वें दौर में यह अनुमान लगाया गया कि 1993-94 से 1999-2000 के दौरान औसतन 47 मिलियन नौकरी के अवसरों की तुलना में 1999-2000 से 2004-05 के दौरान 9.4 मिलियन के वार्षिक औसत से अतिरिक्त काम के अवसर सृजित किए गए। इस अवधि के दौरान रोजगार वृद्धि 2.6 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ी। तथापि, श्रमिक बल में कार्यबल की अपेक्षा 0.2 प्रतिशतांक अधिक तेजी से 2.8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई, जिसमें परिणामस्वरूप 2004-05 में बेरोजगारी दर में 8.3 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। मौजूदा दैनिक प्रास्थिति दृष्टिकोण पर आधारित ये दरें सामान्य प्रास्थिति और साप्ताहिक प्रास्थिति दृष्टिकोणों से प्राप्त दरों की तुलना में अधिक हैं। जो आवर्तक बेरोजगारी की अधिक संख्या को इंगित करता है। सामान्य प्रमुख तथा सहायक प्रास्थिति आधार के अनुसार व्यक्तियों की संख्या की दृष्टि से मापी गई बेरोजगारी की दर 2004-05 में 2.5 प्रतिशत थी।

9. समान प्रत्यावर्तन (रिकॉल) अवधि के अनुसार कुल आबादी में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का अनुपात 1993-94 में 36 प्रतिशत से घट कर 2004-05 में 28 प्रतिशत रह गया। मिश्रित रिकॉल अवधि के आधार पर, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1999-2000 में 26 प्रतिशत से घटकर 2004-05 में 22 प्रतिशत रह गई। इसके अतिरिक्त, 1993-94 और 2004-05 के बीच (एनएसएसओ का 61वां दौर) स्थिर मूल्यों पर औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय में वृद्धि भी मोटे तौर पर विभिन्न ग्रामीण और शहरी आय वर्गों के बीच समान वृद्धि दर्शाती है, यद्यपि इसमें ग्रामीण आबादी की बजाए शहरी आबादी में कम एकरूपता हो सकती है।

### मुद्रास्फीति और मुद्राआपूर्ति

10. जून, 2006 में प्राथमिक वस्तुओं और खनिज तेलों के मूल्यों में वृद्धि के परिणामस्वरूप 2006-07 में मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी हुई। मुद्रास्फीति की दर 27 जनवरी, 2007 को 6.7 प्रतिशत थी और मौजूदा वर्ष के प्रथम सप्ताह, 7 अप्रैल 2007 को यह 6.4 प्रतिशत थी। परन्तु जून, 2007 के बाद से मुद्रास्फीति में कई कारणों से कमी आना आरम्भ हुआ। इनमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नवम्बर, 2006 के अंत में और मध्य फरवरी, 2007 में कमी करके उन्हें जून 2006 के पूर्व के स्तरों पर लाना, प्राथमिक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार तथा राजकोषीय और मौद्रिक उपाय शामिल हैं। मुद्रास्फीति की वर्षानुवर्ष दर 67 सप्ताह के अंतराल के बाद मध्य अगस्त 2007 में घट कर 4 प्रतिशत से कम रह गई। उसके बाद से कुल मिलाकर मुद्रास्फीति 26 जनवरी, 2008 और 2 फरवरी 2008 को 4.1 प्रतिशत तक पहुंचने से पूर्व लगातार 23 सप्ताह तक 4 प्रतिशत से नीचे बनी रही। प्राथमिक वस्तुएं जो 2006-07 में और वर्तमान वर्ष के पहले पांच महीनों में मुद्रास्फीति में बहुत अधिक वृद्धि का कारण थीं, मुद्रास्फीति की दर में गिरावट का भी प्रमुख कारण थीं। भिन्न-भिन्न स्तर पर, 19 जनवरी, 2008 को, 29.7 प्रतिशत भारांश युक्त 132 'विनिर्मित उत्पादों', 10.1 प्रतिशत भारांश वाले 'ईंधन और विद्युत' की 10 मदों और 6.8 प्रतिशत भारांश वाले 41 प्राथमिक वस्तुओं के मूल्य एक वर्ष के पूर्व के स्तर के बराबर अथवा उससे नीचे थे। इन 183 वस्तुओं का कुल भारांश 46.6 प्रतिशत था। इन वस्तुओं ने मौजूदा वर्ष में मुद्रास्फीति में कमी लाने में काफी अधिक योगदान किया।

11. सरकार ने नियमित आधार पर वस्तुओं के मूल्यों पर करीबी नजर रखी और पिछले डेढ़ साल में किए गए उपायों से मूल्य स्थिरता बनाए रखने में मदद मिली। मूल्यों की नजदीकी मानिट्रिंग और उपयुक्त नीतिगत उपायों से घरेलू उपभोक्ताओं पर वैश्विक मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिली।

12. भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति संबंधी दृष्टिकोण ने अर्थव्यवस्था को उच्चतर विकास के रास्ते पर ले जाने और मुद्रास्फीतिकारी दबावों को नियंत्रित करने के बीच संतुलन बनाना जारी रखा। वृहद मुद्रा (एम<sub>3</sub>) की वार्षिक औसत वृद्धि जो 2003-04 में 13 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गई थी, तब से इसमें वृद्धि की प्रवृत्ति बनी हुई है और यह 2006-07 में 19.5 प्रतिशत पर पहुंच गई। 2007-08 में एम<sub>3</sub> के स्टॉक में संचयी (आज की तारीख तक वित्त वर्ष) वृद्धि भी 2006-07 में संचयी वृद्धि से अधिक बनी हुई है और यह

5 जनवरी, 2006 को 12.2 प्रतिशत की तुलना में 4 जनवरी, 2008 को 13.3 प्रतिशत थी। अतः मुद्रास्फीति से एम<sub>3</sub> की वार्षिक या प्रवृत्ति दर, जिसमें इस अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति सही है, को जोड़ना कठिन है। यह संभवतः इस समय चल रही अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के मौद्रिक सुदृढीकरण की समानान्तर प्रक्रिया के कारण है। मुद्रास्फीति के विपरीत, औसत ऋण वृद्धि 2006-07 में मामूली रूप से 26.8 प्रतिशत तक की मंदी आई और 2007-08 में इसमें और अधिक गिरावट आयी। 4 जनवरी, 2008 तक गैर-खाद्य ऋण में संचयी वृद्धि 11.8 प्रतिशत थी, जो 2007 की इसी तारीख तक 17.5 प्रतिशत वृद्धि की अपेक्षा काफी धीमी थी, यह आंशिक रूप से विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों की वृद्धि में गिरावट और इसके परिणामस्वरूप ऋण की मांग में कमी के कारण हो सकता है।

13. 91-दिवसीय और 364-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर अधिकतम आय द्वारा यथामापित नामिनल ब्याज दरों में भी मुद्रा वृद्धि के समान प्रवृत्ति दिखाई दी है। 364-दिवसीय (91-दिवसीय) राजकोषीय हुंडियों पर अधिकतम आय का औसत 2006-07 के दौरान 7.0 (6.6) प्रतिशत रहा। इस आय में अप्रैल-दिसम्बर, 2006 में 6.8 (6.3) प्रतिशत से अप्रैल-दिसम्बर, 2007 में औसतन 7.5 (7.0) प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। 364 (91)-दिवसीय राजकोषीय हुंडियों पर थोक मूल्य सूचकांक में पिछले 12 माह की वृद्धि का प्रयोग करके मापी गई वास्तविक अधिकतम आय, अप्रैल-दिसम्बर, 2006 में 1.7 (1.2) प्रतिशत से लगभग दुगुनी (से अधिक) होकर 3.2 (2.7) प्रतिशत के औसत पर पहुंच गई। वास्तविक ब्याज दर को दुगुना करने से ऋण मांग में मंदी आने की सम्भावना है और परिणामस्वरूप इसका असर मुद्रास्फीति तथा विकास पर पड़ेगा। यह घरेलू और वैश्विक दरों के बीच ब्याज विभेदक को व्यापक आकार देने का कारण भी बनेगा।

### वैदेशिक क्षेत्र

14. वर्ल्ड इकॉनॉमिक आउटलुक (डब्ल्यूईओ अक्टूबर, 2007) में 1970 के दशक के प्रारम्भ से अब तक सर्वाधिक 5 प्रतिशत की औसत वैश्विक विकास दर सहित हाल के विस्तारी चरण का उल्लेख किया गया है। तथापि, डब्ल्यूईओ को जनवरी, 2008 तक अद्यतन कर इन अनुमानों में संशोधन करते हुए इसकी गिरावट को प्रदर्शित किया गया है। अमरीका में आवास क्षेत्र में मंदी और सब-प्राइम बंधक बाजार संकट की वजह से वैश्विक विकास के जोखिम में गिरावट से मूल्यांकन में पर्याप्त अनिश्चितता है। अमरीका तथा अन्य विकसित देशों की मौद्रिक नीति सम्बन्धी कार्रवाइयों से इसके त्वरित प्रभाव को नियंत्रित कर लेना प्रतीत होता है।

15. भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 के दशक के सुधारों से तेजी से उदारीकरण की दिशा में बढ़ रही है। व्यापार जो वैश्विक एकीकरण का एक महत्वपूर्ण आयाम है, में सकल घरेलू-उत्पाद (जीडीपी) के अनुपात के रूप में निरन्तर बढ़ोतरी हुई। आन्तरिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश ने गति पकड़ी है और बाह्य निवेश में तेजी आयी है। वर्ष 2007-08 में पूंजी प्रवाह में तेजी देखी गयी। जीडीपी के अनुपात के रूप में पूंजी प्रवाह जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गतिविधियों के बढ़ते प्रभाव का सूचक है, के सुस्पष्ट बढ़ने की प्रवृत्ति रही है और 2006-07 में जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच गया। यह सुधरते निवेश माहौल का स्वाभाविक परिणाम है और भारत के ठोस व्यापक आर्थिक मूलभूत तत्वों को स्वीकारता है।

16. भले ही वैदेशिक स्तर पर माहौल उत्साहवर्धक रहा, लेकिन बढ़ते अन्तर्प्रवाह और विनिमय दर में बढ़ोतरी की वजह से खुले पूंजी लेखे के प्रबन्धन की समस्या पैदा हुई है। वित्त पोषण की आवश्यकता बढ़ते हुए पूंजी अन्तर्प्रवाह सहित प्रारक्षित निधि में 2006-07 में 36.6 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार, वर्ष 2006-07 की दूसरी छमाही से रूपए में ऊपरी दबाव पड़ा। पूंजी अन्तर्प्रवाह का आधिक्य 2007-08 की पहली छमाही में बढ़कर जीडीपी का 7.7 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष में विदेशी विनिमय प्रारक्षित निधियों में 91.6 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ोतरी हुई, अभी तक यह 8 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार 290.8 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। प्रारक्षित निधियों की तीव्र अनुवृद्धि और रूपए पर बढ़ते प्रभाव से बाजार स्थिरीकरण योजना के सम्बन्ध में सीमाओं में बढ़ोतरी करना आवश्यक हो गया। वर्ष 2007-08 में अन्तर्प्रवाह अवरुद्धता की संशोधित राजकोषीय लागत 8,200 करोड़ रूपए है। सापेक्ष तौर पर खुले पूंजी लेखे के संतुलन, मौद्रिक नीति स्वतंत्रता और लोचशील विनिमय दर के लिए सम्मिश्र उपयुक्त नीति जारी रहेगी।

17. पूंजी प्रवाह की संरचना में भी परिवर्तन हो रहा है। वर्धित पूंजी प्रवाह की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अन्तर्प्रवाह में 150 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना था जो 2006-07 में 23 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। चालू वित्त वर्ष में यह प्रवृत्ति जारी रहेगी जबकि पहले छह माह में सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) प्रवाह 11.2 बिलियन अमरीकी डालर हो जाएगा। एफडीआई अन्तर्प्रवाह व्यापक थे और वित्तीय सेवाओं, विनिर्माण, बैंकिंग सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं और निर्माण जैसी कई आर्थिक गतिविधियों में विस्तार लिए हुए थे। पिछले दो साल भारतीय-बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण साबित हुए जबकि भारतीय उद्यमों के वैश्वीकरण का सूत्रपात हुआ। भारत से बाह्य निवेश में बढ़ोतरी होकर यह वर्ष 2006-07 में 14.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जबकि 2003-04 में यह लगभग 2 बिलियन अमरीकी डालर था और यह प्रवृत्ति अप्रैल-सितम्बर, 2007 में 7.3 बिलियन अमरीकी डालर के बाह्य निवेश सहित चालू वर्ष में जारी रही। एशियाई तथा वैश्विक वित्तीय बाजारों में वर्ष 2006-07 में बढ़ती तेजी ने पोर्टफोलियो निवेश के प्रवाह को प्रभावित किया। निवल प्रवाह वर्ष 2005-06 में 12.1 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2006-07 में 7.1 बिलियन अमरीकी डालर थे। यूरो इक्विटी जो सापेक्षतया पोर्टफोलियो प्रवाह का लघु संघटक थी, (वर्ष 1997-98 से 2004-

05 की अवधि में 1 बिलियन अमरीकी डालर से कम), बढ़कर वर्ष 2006-07 में 3.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गई और ये कुल निवल पोर्टफोलियो प्रवाह का 54.3 प्रतिशत हैं। अप्रैल-सितंबर, 2007 में निवल पोर्टफोलियो निवेश अन्तर्प्रवाह 18.3 बिलियन डालर था जो वर्ष 2006-07 के दौरान अन्तर्प्रवाह का दोगुना था। पोर्टफोलियो निवेश में तेजी के बावजूद, हाल के वर्षों में किसी भी वर्ष में अधिकतम निवल बाह्य प्रवाह वर्ष 1998-99 में 219 मिलियन अमरीकी डालर पर नगण्य था।

18. चालू खाता घाटा (सीएडी) राष्ट्रीय आय लेखे में बचत-निवेश अन्तराल को प्रदर्शित करता है और इस प्रकार विदेशी बचतें बनता है। जीडीपी के अनुपात के रूप में चालू खाता शेष में बढ़ोतरी और गिरावट मुख्यतः वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार शेष द्वारा निरंतर संचालित होती रही। तथापि, विप्रेषणों सहित उपादान लागत से उत्पन्न अधिशेष ने, जो जीडीपी के 2 और 3 प्रतिशत के बीच घट-बढ़ होता रहा, व्यापार खाते में घाटे को कम करने में सहायता प्रदान की।

19. जीडीपी अनुपात के रूप में व्यापार में जो खुले व्यापार का संकेतक है, वर्ष 2000-01 में जीडीपी के 22.5 प्रतिशत से बढ़ोतरी होकर यह 2006-07 में जीडीपी का 34.8 प्रतिशत हो गया। यदि सेवा व्यापार को शामिल किया जाए तो यह अनुपात बढ़कर 2006-07 में जीडीपी का 48 प्रतिशत हो जाएगा। भारत का पण्य निर्यात और आयात (सीमा शुल्क आधार पर अमरीकी डालर में) वर्ष 2006-07 में क्रमशः 22.6 प्रतिशत और 24.5 प्रतिशत तक बढ़ गए। चालू वर्ष के पहले नौ महीनों में, निर्यात में 21.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 111 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया जो वर्ष के निर्यात लक्ष्य का लगभग 70 प्रतिशत है। अप्रैल-सितंबर, 2007 के दौरान निर्यात वृद्धि के मुख्य वाहक पेट्रोलियम उत्पाद, इन्जीनियरिंग सामान और रत्न तथा जवाहरात थे। आयात में अप्रैल-दिसंबर, 2007 के दौरान 25.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई जबकि विनिर्माण क्षेत्र की ठोस औद्योगिक मांग और निर्यात गतिविधि से संसूचित पेट्रोलियम तेल स्नेहक-भिन्न आयात में 31.9 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई। अप्रैल-दिसंबर, 2007 में पण्य व्यापार घाटा 57.8 बिलियन अमरीकी डालर था जो वर्ष 2006-07 (पूर्ण वर्ष) के 59.4 बिलियन अमरीकी डालर के व्यापार घाटे के काफी निकट था।

वर्ष 2006-07 में भारत का सेवा निर्यात 32.1 प्रतिशत से बढ़कर 76.2 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। सॉफ्टवेयर सेवाएं, व्यापार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और संचार सेवाएं विकास के मुख्य संचालक थे। वर्ष 2006-07 में वाणिज्यिक सेवा निर्यात पण्य निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत था। अप्रैल-सितंबर, 2007 में सेवा निर्यातों में सॉफ्टवेयर-भिन्न सेवाओं विशेषकर व्यापार और संचार सेवाओं में गिरावट के कारण 8.6 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

### रुपए का अधिमूल्यन

20. विदेशी मुद्रा (भुगतान संतुलन का नामे पक्ष) की बढ़ती मांग और विदेशी मुद्रा (भुगतान-सन्तुलन का क्रेडिट पक्ष) की पर्याप्त आपूर्ति न होने के कारण 3 अप्रैल, 2007 और 6 फरवरी, 2008 के बीच चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रुपए का डालर के मुकाबले 8.9 प्रतिशत अधिमूल्यन हुआ। विगत बारह माह के दौरान डालर के मुकाबले रुपए का अधिमूल्यन वर्षानुवर्ष आधार पर (दिसम्बर 2006 से दिसम्बर 2007) 13.2 प्रतिशत पर कहीं अधिक था। वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (6मुद्रा, व्यापार आधारित भार) जिससे प्रतिस्पर्द्धियों के सापेक्ष मूल्य स्तरों का गुण खंड निकाल कर वास्तविक प्रतिस्पर्द्धी का पता चलता है, में अप्रैल-जनवरी 2007-08 के दौरान 7.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। डालर की तुलना में रुपए का अधिमूल्यन से निर्यातों की मुख्य बीजक मुद्रा ने प्रतिस्पर्द्धी देशों के निम्नतर अधिमूल्यन के मुकाबले संयुक्त राज्य अमरीका जैसे व्यापार भागीदारों के आयात में धीमी वृद्धि के साथ कुछ ऐसे क्षेत्रों, जहां आयात की मात्रा कम है, के निर्यातों पर प्रभाव डाला। इस प्रभाव को कम करने और समायोजन को आसान बनाने हेतु सरकार ने चुनिंदा क्षेत्रों में राहत उपायों की घोषणा की।

### राजकोषीय समेकन

21. एफआरबीएम पश्च अवधि में राजकोषीय समेकन संबंधी प्रगति संतोषजनक रही है। सघउ के समानुपात में केन्द्र का राजकोषीय घाटा वर्ष 2001-02 के 6.2 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2006-07 (वास्तविक) में 3.4 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2006-07 (वास्तविक) में सकल कर सघउ अनुपात बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गया और वर्ष 2007-08 में सघउ के 11.8 प्रतिशत पर बजटीय व्यवस्था की गई। पहले नौ माह के दौरान सकल कर प्राप्तियों में 27.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजट अनुमानों में इनका भाग 71 प्रतिशत था। राजस्व व्यय में 13.6 प्रतिशत (अप्रैल-दिसम्बर 2007) की वृद्धि हुई और बजट अनुमानों में इसका भाग 71 प्रतिशत था। पूंजी व्यय में 120 प्रतिशत की वर्षानुवर्ष वृद्धि के साथ अत्यधिक उछाल आया जोकि मुख्यतया भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित भारतीय स्टेट बैंक की इक्विटी के अर्जन संबंधी सौदे के कारण हुआ। राजस्व और राजकोषीय घाटा बजट अनुमानों का क्रमशः 55 प्रतिशत और 51 प्रतिशत रहा।

### संभावनाएँ

22. हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास से भौतिक और सामाजिक आधारभूत ढांचे के विकास की तत्काल आवश्यकता को और अधिक बल मिला है। स्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि विद्युत, रेलवे, सड़कों, वायुपत्तनों, पत्तनों और संचार जैसे भौतिक आधारभूत ढांचे में निवेश का परिमाण और गुणवत्ता में तीव्र वृद्धि हो रही है। भौतिक आधारभूत ढांचे के विकास हेतु सरकारी-निजी भागीदारियों

को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना पर भी विचार किया जा रहा है और इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की आशा है। ग्यारहवीं योजना में आधारभूत ढांचा क्षेत्र के विकास के एक व्यापक कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार की गई है।

23. सुस्पष्ट 'जनसांख्यिकीय लाभ' स्वयं इस तथ्य को उजागर करता है कि 15 से 64 वर्ष की कार्यशील आबादी में वर्ष 2006 के 62.9 प्रतिशत से बढ़ोतरी होकर यह वर्ष 2026 में 68.4 प्रतिशत हो जाएगा। इस लाभ को नियोजित करने हेतु ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य देखभाल, रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन तथा दक्षता विकास व्यक्तियों की नियोजनीयता में सुधार सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

24. आज अर्थव्यवस्था के स्थायी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास, के लिए परिस्थियां अनुकूल हैं। भारत के निजी क्षेत्र का आर्थिक उदारीकरण और वर्द्धित अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति अनुक्रियाशीलता सामान्यतः संतोषजनक रही है तथा इससे अर्थव्यवस्था में अत्यधिक लोचनीयता आई है। हाल के समय में मांग का घटता-बढ़ता स्वरूप उत्पादनकारी क्षमता में बढ़ोतरी का संकेत है, जिसके अर्थव्यवस्था की उच्च विकास दर में सहायक होने की संभावना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से कृषि विकास के अधिक गति पकड़ने की आशा है। निवेश सामान्यतः अग्रवर्ती परिवर्तनीय घटक है और इसकी वृद्धि से मध्यावधि में विकास की संभावना सुदृढ़ होगी।

वृहत आर्थिक रूपरेखा विवरण  
(आर्थिक कार्य निष्पादन : एक दृष्टि में)

क्र.सं.	मद	निरपेक्ष मूल्य		प्रतिशत परिवर्तन	
		अप्रैल-दिसंबर 2006-07	2007-08	अप्रैल-दिसंबर 2006-07	2007-08
<b>वास्तविक क्षेत्र</b>					
1.	कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (हजार करोड़ रुपए)*				
	(क) वर्तमान मूल्यों पर	3790.1	4283.0	15.7	13.0
	(ख) 1999-2000 के मूल्यों पर	2864.3	3114.4	9.6	8.7
2.	औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक (1)	239.8	261.4	11.2	9.0
3.	थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1993-94=100) (2)	208.7	216.0	5.9	3.5
4.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) (3)	127.0	134.0	6.9	5.5
5.	मुद्रा आपूर्ति (एम <sub>3</sub> ) (हजार करोड़ रुपए)\$	3016.3	3702.8	19.3	22.8
6.	वर्तमान मूल्यों पर आयात**				
	(क) करोड़ रुपए	611522	682088	31.2	11.5
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	134080	168803	27.3	25.9
7.	वर्तमान मूल्यों पर निर्यात**				
	(क) करोड़ रुपए	416176	448377	28.7	7.7
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर	91249	110965	24.8	21.6
8.	व्यापार घाटा (मिलियन अमरीकी डालर)**	-42831	-57838	32.9	35.0
9.	विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां				
	(क) करोड़ रुपए में	752738	1050485	27.5	39.6
	(ख) मिलियन अमरीकी डालर में	170187	266553	29.2	56.6
10.	चालू लेखा संतुलन (मिलियन अमरीकी डालर में) @	-10340	-10713		
<b>सरकारी वित्त साधन #</b>					
1.	राजस्व प्राप्तियां	280915	355646	29.6	26.6
2.	कर राजस्व (निवल)	232171	295994	37.6	27.5
3.	कर-भिन्न राजस्व	48744	59652	1.5	22.4
4.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6+7)	102806	118607	-11.2	15.4
5.	ऋणों की वसूली	7952	3304	7.3	-58.5
6.	अन्य प्राप्तियां	0	37725	-100.0	
7.	उधार और अन्य देनदारियां	94854	77578	-12.4	-18.2
8.	कुल प्राप्तियां (1+4)	383721	474253	15.4	23.6
9.	आयोजना-भिन्न व्यय	272203	337090	14.4	23.8
10.	राजस्व लेखा	253791	280050	14.6	10.3
<i>जिसमें:</i>					
11.	ब्याज भुगतान	92634	111764	14.4	20.7
12.	पूंजी खाता	18412	57040	12.6	209.8
13.	आयोजना व्यय	111518	137163	17.9	23.0
14.	राजस्व खाता	93901	114806	25.4	22.3
15.	पूंजीगत खाता	17617	22357	-10.7	26.9
16.	कुल व्यय (9+13)	383721	474253	15.4	23.6
17.	राजस्व व्यय (10+14)	347692	394856	17.3	13.6
18.	पूंजी व्यय (12+15)	36029	79397	-0.1	120.4
19.	राजस्व घाटा (17-1)	66777	39210	-16.2	-41.3
20.	राजकोषीय घाटा {16-(1+5+6)}	94854	77578	-12.4	-18.2
21.	प्रारम्भिक घाटा (20-11)	2220	-34186	-91.9	-1639.9

अ.अ. - अग्रिम अनुमान

त्व.अ.- त्वरित अनुमान

\*पूर्ण वर्ष से संबंधित है।

1. आधार 1993-94= 100

2. दिसंबर के अंतिम सप्ताह में (बिंदु दर बिंदु)

3. दिसंबर के अंत में (बिंदु दर बिंदु)

# महालेखा नियंत्रक, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा यथासूचित आंकड़े

\$ आंकड़े 21 दिसंबर, 2007 से संबंधित हैं।

\* भारतीय स्टेट बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के पण्य की बिक्री के लाभ के अंतरण के कारण 34,308.6 करोड़ रुपए की राशि शामिल है।

\*\* सीमाशुल्क आधार पर वर्तमान वर्ष की तुलना अनन्तिम से अनन्तिम आधार पर है।

@ अवधि अप्रैल-सितंबर से संबंधित है।